The Hindu- 16- October-2022

First flood warning issued at Prakasam Barrage, low-lying areas face threat

Tharun Boda
VIJAYAWADA

The low-lying areas in Krishna and NTR districts of Andhra Pradesh are once again facing the threat of inundation as the Krishna river is in spate. The first flood warning has been issued by the authorities concerned on October 15 as the flood discharge at Prakasam Barrage touched 3.97 lakh cusecs in the early hours and reached 4.5 lakh cusecs by 9 a.m. as per the Water Resources Department website.

The discharge was steady at 4.5 lakh cusecs at 5 p.m. The first flood warning was issued for the fourth time this year since August and several areas bore the brunt of the floods.

Several areas alongside the river course in NTR and Krishna districts have been flooded since Friday night. Water entered residential areas of Ranigari Thota and others in Krishnalanka following the rise in the flood level.

The Andhra Pradesh State Disaster Management Authority (APSDMA) has alerted the officials of the districts concerned in view of the rising flood level in Krishna. In a release, APSDMA managing director B.R. Ambedkar said that the flood level was likely to rise further and asked the people residing in low-lying areas to take necessary precautions. He asked the authorities concerned to stay alert.

The second and last flood warning would be issued when the flood discharge crosses 5.69 lakh cusecs.

Beyond limits: Floodwater being dischared from Prakasam Barrage in Vijayawada on Saturday. G.N. RAO

Dainik Jagran- 16- October-2022

समय पर न चेतने के दुष्परिणाम

संजय गुप्त

यदि प्रदूषण की विभीषिका से बचना है तो सरकार और जनता, दोनों को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी

दशहरे के बाद उत्तर भारत में हुई बेमौसम बरसात ने प्रदूषण के दुष्प्रभाव को कुछ दिनों के लिए कम अवश्य कर दिया, लेकिन वर्षा बंद होने के बाद से उत्तर-पश्चिम भारत में प्रदूषण की मार को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सर्दियां शुरू होते ही लगभग पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में वायु प्रदूषण सिर उठा लेता है और फिर समय के साथ व्यापक होता जाता है। प्रदूषण की शुरुआत भले ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से होती हो, लेकिन धीरे-धीरे उसमें अन्य कारक भी अपना योगदान देने लगते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में वर्षों से पराली जलाई जा रही है। 15-20 वर्ष पहले तक तो सरकारें पराली जलाने को प्रदूषण का कारण मानती ही नहीं थीं, पर जबसे वैज्ञानिक तरीके से इसे स्थापित किया गया कि कम से कम उत्तर-पश्चिम भारत के एक हिस्से में पराली का धुआं प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है, तबसे सरकारें इसे लेकर सजग हुईं। इस सजगता के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

प्रदूषण के चलते जो तमाम हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती हैं, उनके कारण जलवायु परिवर्तन तेज होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से कई गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं-न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में। जलवायु परिवर्तन के चलते आने वाले दशकों में फसल चक्र भी संकट में आ सकता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी सारी किसानी मानसून की वर्षा पर आधारित है। यह देखा जा रहा है कि असमय वर्षा के कारण किसानों को अपना फसल चक्र बनाए रखना कठिन हो रहा है। भविष्य में ये कठिनाइयां और बढ़ सकती हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पर्यावरण प्रदूषित होने से फसल चक्र प्रभावित होने के साथ और भी कई घातक असर पड़ते हैं। यह मानव स्वास्थ्य पर भी व्यापक असर डालता है। प्रदूषण जनित बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। जिस तरह सिगरेट का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसी तरह पराली का धुआं भी बहुत घातक साबित होता है। विडंबना यह है कि पराली को जलने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम सक्रियता सितंबर-अक्टूबर में ही दिखती है। इस बार भी जब पंजाब और हरियाणा में पराली जलने लगी, तब सरकारें चेतीं। आखिर वे समस्या के सिर उठाने का इंतजार क्यों करती हैं और बाकी समय हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठी रहती हैं? समय से न चेतने के कारण पराली को जलाने से रोकने में सीमित सफलता ही मिली है। पराली खेतों में न जलाई जाए, इसके विकल्प तो मौजूद हैं, पर उन पर अमल के मामले में सरकारें कितनी

अखिलेश राजपूत

हीलाहवाली करती हैं, यह इससे स्पष्ट होता है कि पराली जलाना शुरू हो जाने के बाद केंद्र सरकार ने पराली से पैलेट यानी एक तरह का कोयला बनाने की एक परियोजना शुरू की। यह जब तक जमीन पर उतरेगी तब तक तो पराली जल चुकी होगी। हां, यदि यह परियोजना ठीक से लागू की जाए तो अगले वर्ष तक इसका पूरा लाभ मिल सकता है।

यह किसी से छिपा नहीं कि पराली जलाने वाले किसान और अन्य अनेक लोग प्रदूषण की विभीषिका को अपनी समस्या नहीं मानते। औसत किसान न तो पराली जलाने से होने वाले नुकसान की चिंता करते हैं और न ही गिरते भूजल स्तर के बाद भी अधिक पानी की मांग वाली फसलें उगाने से बचते हैं। आखिर उन इलाकों में धान की खेती क्यों होती है, जहां उसकी खपत नहीं होती? शायद सरकारें अभी तक पराली जलाने और पानी की अधिक मांग वाली फसलें उगाने से पैदा होने वाली समस्याओं से किसानों को सही तरह अवगत नहीं करा सकी हैं। इसी तरह वे आम आदमी को प्रदूषण रोकने के तौर-तरीके अपनाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकी हैं। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है, जिसका समाधान तभी संभव होगा, जब सरकारों को जनता का भी सहयोग मिलेगा। यह भी समझना होगा कि उत्तर भारत में पराली का धुआं प्रदूषण का एक बड़ा कारक अवश्य है, लेकिन उसके साथ ही वाहनों का उत्सर्जन, सड़कों और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल, कारखानों से निकलने वाला धुआं आदि भी प्रदूषण बढ़ाने का काम करते हैं।

उत्तर भारत में सर्दियों में जब भी प्रदूषण की बात होती है तो सबसे पहले पराली सबके मस्तिष्क में आती है, लेकिन वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, सड़कों से उड़ती धूल और कारखानों से निकलने वाले धुएं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता। वास्तव में इसी कारण प्रदूषण पर प्रभावी लगाम नहीं लग पाती। यदि यह सोचा जा रहा है कि केवल दंडात्मक उपायों से पराली को जलने से रोका जा सकता है तो यह सही नहीं। इसी तरह यदि शहरी इलाकों में यातायात को सुगम बनाने के लिए अकेले फ्लाइओवर बनाने से सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होता तो दिल्ली-एनसीआर में ऐसा न जाने कब हो जाता। यहां लगातार फ्लाइओवर और अंडरपास बन रहे हैं, लेकिन प्रदूषण नहीं थम रहा है। जिन इंजीनियरों, योजनाकारों और नीति-नियंताओं पर यह जिम्मेदारी है कि वे शहरों के अंदर आधारभूत ढांचे को अधिक बेहतर बनाएं, उन्हें और सजग होना होगा एवं वैज्ञानिक तरीके अपनाकर प्रदूषण नियंत्रण का काम करना होगा। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि शहरों में आधारभूत ढांचे के निर्माण की गति तो अत्यधिक धीमी है ही, निर्माण की परंपरागत प्रक्रिया भी प्रदूषण को बढ़ाने वाली है। अभी भी पुरानी तकनीक अपनाकर शहरों के आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। इससे भी प्रदूषण फैलता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत का जो नारा अपने पहले कार्यकाल में दिया था, उसका कुछ समय तक तो असर रहा, पर अब धीरे-धीरे वह समाप्त-सा हो गया है। आम नागरिक प्रदूषण निवारण के मामले में पूरी तरह सरकारों पर निर्भर हैं। अपवाद के तौर पर भारत के कुछ शहर जरूर साफ दिखते हैं, लेकिन अधिकांश शहरों में धूल-धुआं और गंदगी आम है। यदि प्रदूषण की विभीषिका से बचना है तो सरकार और जनता, दोनों को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी। चाहे पराली जलाने पर लगाम लगाने की बात हो या फिर शहरों के अंदर धूल और धुएं पर नियंत्रण की, इन सब पर बहुत तेजी और प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है।

response@jagran.com

Rajasthan Patrika- 16- October-2022

घाघरा नदी ने दिखाया रौद्र रूप

65 गांव में बाढ़ की तबाही

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

आजमगढ़. उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी का कहर बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में घाघरा नदी के पानी से रिंग बांध कटने के कारण लगभग 65 गांवों के सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं।

आजमगढ़ जिला प्रशासन के अनुसार जिले की सगड़ी तहसील क्षेत्र के देवरांचल में बहने वाली घाघरा नदी के जलस्तर ने पिछले 24 साल का रिकार्ड तोड़ दिया। घाघरा नदी खतरा बिन्दु से 1.91 मीटर उपर बह रही है। महुला से हैदराबाद तक बांध में कई स्थानो पर रिसाव शुरू होने की जानकारी मिल रही है। वहीं छितौनी गांव के पास नदी का पानी बांधे के बराबर बहने से ग्रामीणों डरे सहमे है। महुला गढ़वल के पास तेज बहाव के चलते रिंग बांध का काफी हिस्सा कट गया है। रिस्त्रा को रोकने के लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी को उतार दिया गया, वहीं ग्रामीण भी अपना सहयोग कर रहे है।

आजमगढ़ के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने शनिवार को बताया कि बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बाढ़ प्रभावित गांवों के प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में ले पहुंचाया गया है। मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी (सपा) के क्षेत्रीय विधायक नफीस अहमद ने प्रशासन द्वारा दी जा रही राहत को नाकाफी बताया है। उन्होंने नदी का पानी कम होने की उम्मीद जतायी है। उन्होने कहा कि रिसाव को रोकी करने के लिए अधिकारी व कर्मचारी लगे है। कोई परेशानी की बात नही है। वहीं गोपालपुर विधानसभा के सपा विधायक नफीस अहमद ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, कहा कि सबको पता है कि देवरांचल में हर बार नेपाल जब पानी छोड़त है तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है ऐसे में सरकार व प्रशासन को सभी तैयारियों को पहले ही पूर्ण कर लेनी चाहिए थी।

सरयू नदी का जल स्तर स्थिर, नेपाल से पानी आना कम हुआ

बस्ती @ पत्रिका. उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में शनिवार को सरयू नदी के जल स्तर में गिरावट दर्ज की गयी है। नदी का जल स्तर लगभग 19 सेमी कम हुआ है, उधर नेपाल की तरफ भी नदी में पानी आना कम हो गया है। जिला प्रशासन ने हालांकि बाढ़ की स्थिती जस की तस बनी होने की पुष्टि की है। बाढ़ खण्ड और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बाढ़ क्षेत्रों मे लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन की ओर से शनिवार को बताया गया कि सरयू नदी में नेपाल से पानी आना कम हो गया है सरयू नदी का जल स्तर खतरे के निशान से लगभग 105 सेमी ऊपर है। बीते कुछ समय में नदी का जल स्तर लगभग 19 सेंमी कम हुआ है। बाढ़ के पानी से 95 गांव घिरे हुए है। ग्राम पंचायत अशोकपुर, माझा जाने वाला संपर्क मार्ग पूरी तरह से ओवरफ्लो है। जहां आने जाने वाले ग्रामीणों को पुलिस रोक रही है। तटबंध व सरयू के बीच बसे गांवो में बाढ़ की तबाही बरकरार है।

बाढ़ से प्रभावित 60 गांव में 300 नावें लगाई

अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह ने बाढ़ क्षेत्र सगड़ी का निरीक्षण करते हुए बताया कि तहसील सगड़ी अंतर्गत बाढ़ से कुल 65 गांव प्रभावित हैं। इन गांवों की जनसंख्या 65 हजार है। इनमें से 12 गांव की आबादी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुई है। इन गांव के 1500 लोगों को राहत शिविरों में लाया गया है। लोगों को राहत कैंपों में पहुंचाने एवं भोजन इत्यादि की व्यवस्था कराई जा रही है। सगड़ी के उपजिलाधिकारी राजीव रत्न सिंह भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाढ़ से प्रभावित 60 गांव में करीब 300 नावें लगाई हैं।